विश्व बैंक से सहयोग से संचालित होगी 3,903 करोड़ की परियोजना

- दिसंबर तक विश्व बैंक का निदेशक मंडल परियोजना को देगा मंजूरी
- मुख्य सचिव ने आर्थिक मामलों के विभाग और विश्व बैंक के अधिकारियों के समक्ष दी प्रस्तुति

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ : उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादकता की असमानता को दूर करने के साथ-साथ मजबूत डिजिटल प्लेटफार्म विकसित करने के उद्देश्य से शुरू की जा रही उत्तर प्रदेश कृषि विकास और ग्रामीण उद्यम पारिस्थितिकी तंत्र सुदृढ़ीकरण (यूपी एग्रीस) परियोजना को विश्व बैंक का पूरा सहयोग मिलेगा। शुक्रवार को नई दिल्ली में वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए) की बैठक में विश्व बैंक से सहयोग से संचालित होने वाली 3,903 करोड़ रुपये की यूपी एग्रीस परियोजना को सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई।

भारत में विश्व बैंक के कंट्री डायरेक्टर अगस्टे तानो कौमे ने इस परियोजना को लागू करने में उत्तर प्रदेश सरकार को हर सहयोग देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक मंडल द्वारा दिसंबर 2024 तक परियोजना को स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी। बैठक में मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका और 2030 तक यूपी को वन ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य को साझा करते हुए यूपी एग्रीस पर प्रस्तुति दी। उन्होंने बताया कि छह वर्षों तक संचालित होने वाली इस परियोजना के तहत फसल उत्पादकता को बढ़ावा देकर, उच्च मूल्य वाली वस्तुओं के लिए क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे। राज्य के पूर्वी और बुंदेलखंड क्षेत्रों में मत्स्य पालन पारिस्थितिकी तंत्र को भी इसके तहत मजबूत किया जाएगा। वहीं, राज्यव्यापी डिजिटल प्लेटफार्म विकसित कर और कृषि तंत्र को सुदृढ़ किया जाएगा। मुख्य सचिव की प्रस्तुति को आर्थिक मामलों के विभाग और विश्व बैंक के अधिकारियों से पूरा समर्थन मिला।